

## “एशिया भर के नीति निर्माताओं को लंबे समय तक आर्थिक मंदी का प्रबंधन करने के लिए पर्याप्त उपायों के साथ तैयार रहना होगा।”

जुलाई, 2019 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ने वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक के अपने नवीनतम अपडेट में इस बात की पुष्टि की है कि वैश्विक विकास में गिरावट आई है और निकट भविष्य में काले बादल छा रहे हैं। विशेष रूप से, आईएमएफ ने अक्टूबर, 2018 के बाद से वैश्विक विकास दर को कई बार घटा चुकी है जो अब 2018 में 3.6% की तुलना में 3.2% हो गयी है।

### चीनी कारक

वर्तमान में उन्नत और विकासशील दोनों अर्थव्यवस्थाओं के बीच आर्थिक गतिविधियों में व्यापक रूप से मंदी छाई हुई है, फिर भी हमें चीन पर विशेष ध्यान देना चाहिए। वित्तीय जोखिमों से निपटने सहित, चल रहे आपूर्ति पक्ष में सुधार, टैरिफ में वृद्धि के नकारात्मक प्रभाव और इसके कारण निर्यात और निवेश पर पड़ने वाले प्रभाव के साथ चीन ने विकास को प्राप्त करने के लिए कई समस्याओं का सामना किया है। यह उल्लेखनीय है कि चीन (जापान के साथ जो बेहद प्रतिकूल जनसांख्यिकी का सामना कर रहा है और लगातार अपस्फीति दबावों से बचने में असमर्थ दिख रहा है) उन कुछ प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में से एक है, जिसकी रफ्तार 2020 तक धीमी रहेगी।

जैसा कि कॉर्पोरेट अपनी चीन-केंद्रित आपूर्ति श्रृंखला (दोनों चल रही नीति अनिश्चितताओं और बढ़ती संरक्षणवादी भावनाओं के जवाब में) को फिर से आकार देने की कोशिश में लगे हुए हैं, कई निर्यात-निर्भर एशियाई अर्थव्यवस्थाएं, जो जटिल उत्पादन नेटवर्क का एक हिस्सा हैं, अनिवार्य रूप से उन्हें भी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा।

हालांकि, वियतनाम से चीन जैसे देशों को निर्यात और व्यापार के कुछ अल्पकालिक लाभ प्राप्त हुए हैं, लेकिन वैश्विक स्तर पर मांग में छाई मंदी ने इन लाभों को कम कर दिया है। उदाहरण के लिए, सिंगापुर के छोटे आकार और खुली अर्थव्यवस्था को ध्यान में रखते हुए, हम अक्सर पाएंगे कि यह अक्सर एशिया के बाकी हिस्सों के लिए मंदी के बैरोमीटर के रूप में काम करता है। नवीनतम आंकड़ों से पता चलता है कि इस शहर का निर्यात कमजोर पड़ चुका है और सिंगापुर की अर्थव्यवस्था को 2019 में विनिर्माण क्षेत्र में तीव्र मंदी के कारण ठहराव का सामना करने की उम्मीद है।

### बचाव के लिए एशियाई बैंक

वैश्विक आर्थिक मंदी के साथ-साथ आम तौर पर मुद्रास्फीति के दबावों के कारण, कई एशियाई केंद्रीय बैंकों (भारत, चीन, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, दक्षिण कोरिया) ने मौद्रिक नीति को कम करना शुरू कर दिया है। हालांकि, यह सामान्यीकृत ढीलापन काफी हद तक यू.एस. फेड के हालिया संकेतों के बाद हुआ है, जहाँ संयुक्त राज्य अमेरिका और दुनिया के बाकी हिस्सों में मंदी के जवाब में दर में कटौती का एक नया दौर फिर से शुरू हो गया है। वास्तव में, 10 जुलाई, 2019 को यू.एस. फेड के चेयरमैन जेरोम पॉवेल ने फेड के इस फैसले का कारण वैश्विक विकास में छाई सुस्ती को माना है।

एशिया में दर में कटौती की लहर यह बताती है कि उभरती अर्थव्यवस्थाएं ब्याज दरों को कम करने के बारे में हमेशा सतर्कता तब बरतती हैं, जब आधार देश (आमतौर पर अमेरिका) ऐसा करना नहीं चाहते हैं। इसका कारण यह होता है कि ये संभावित पूंजी वृद्धि और तेज मुद्रा मूल्यहास के बारे में चिंतित रहते हैं और इसके कारण घरेलू फर्मों और अन्य संस्थाओं पर विदेशी मुद्राओं में उधार बढ़ जाता है।

वैकल्पिक रूप से, यदि उभरती अर्थव्यवस्थाएं स्वयं आर्थिक मंदी का सामना कर रही हैं, तो वे आधार देश के साथ अपनी ब्याज दरों को कम करने में सहज हैं, जैसा कि वर्तमान में एशिया में है। इसे सुनिश्चित करने के लिए एशिया भर के नीति निर्माताओं को लंबे समय तक आर्थिक मंदी का प्रबंधन करने के लिए पर्याप्त उपायों के साथ तैयार रहना होगा।

## आरबीआई का मौद्रिक नीति रुख

इन सब मुद्दों पर भारत कहाँ स्थित है। चूंकि भारत एशियाई और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं के साथ अच्छी तरह से एकीकृत नहीं हुआ है, इसलिए भारत पर चीन-यू.एस. ट्रेड वार का सीधा असर नहीं हुआ है। इसके अलावा, मौजूदा तीव्र घरेलू अड़चनों, नीतिगत कमजोरियों और चल रही संरचनात्मक चुनौतियों को देखते हुए, भारत चीन को वैकल्पिक उत्पादन और निर्यात मंच के रूप में महत्वपूर्ण लाभ नहीं दे पाया है।

आईएमएफ ने 2019 में भारत के लिए अनुमानित वृद्धि को 7% तक घटा दिया है। यह मोटे तौर पर भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा पूर्वानुमानित सीमा के अनुरूप है। जबकि यह वृद्धि अन्य प्रमुख देशों के सापेक्ष सराहनीय है, यह देश की संभावित विकास दर 7.5% और 8% से काफी कम है।

वृद्धि में मंदी, नरम मुद्रास्फीति, राजकोषीय अंतराल की कमी और सरकार का आम चुनाव से विचलित होना, आरबीआई द्वारा ब्याज दरों को कम करने का कारण बना।

तेजी से ब्याज दरों में कटौती के बावजूद, भारत की वास्तविक ब्याज दरें अभी भी अधिकांश अन्य देशों की तुलना में अधिक हैं। हालांकि, यह स्पष्ट नहीं है कि वास्तव में भारत के संभावित उत्पादन के अनुरूप तटस्थ वास्तविक ब्याज दर क्या है। जून, 2019 की ब्याज दर में कटौती के बाद आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास का बयान आया कि आरबीआई का नीतिगत रुख 'फिर से 'तटस्थ' से 'समायोजन' में बदल गया है', जो संभवतः यह बताता है कि वह वर्तमान वास्तविक ब्याज दरों को संतुलित करने का विचार कर रहा है। इस क्षेत्र के अधिकांश देशों की तुलना में, भारत के लिए एक निरंतर चिंता की बात यह है कि बैंक दरों के लिए ब्याज दर नीति संचरण धीमा और सीमित हो जाता है। इसके कुछ निम्नलिखित कारण हैं: बैंकिंग प्रणाली को परिसंपत्ति की गुणवत्ता में गिरावट के साथ-साथ बैंड लोन की समस्या का भी सामना करना, जमा वृद्धि में कमी, और जमा दरों को कम करने की सीमित गुंजाइश।

ब्याज दरों में कटौती के बावजूद, भारत की वास्तविक प्रभावी विनिमय दर (आरईआईआर) ने अक्टूबर, 2018 से वास्तव में बेहतर प्रदर्शन किया है (लगभग 7%), जहाँ वास्तविक ब्याज दरों में गिरावट नहीं हुई है। यह एक और चिंता का मुद्दा बाहरी मांग में गिरावट है तथा सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें अनिश्चितता बनी रहने की उम्मीद है।

## सॉवरेन बॉण्ड का मुद्दा

आगे बढ़ते हुए, यदि भारत को 2024-25 तक 5-ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने की अपनी महत्वाकांक्षा को सफल बनाना है, तो निजी निवेश और लंबी अवधि के विकास को शुरू करने के लिए आवश्यक संरचनात्मक सुधारों को शुरू करने के अलावा और कोई विकल्प नहीं है।

धीमी अर्थव्यवस्था में राजस्व बढ़ाने के संदर्भ में व्याप्त बाधाओं के कारण, सरकार का पसंदीदा समाधान विदेशी सब्सिडी और राजस्व व्यय के बजाय विदेशी सॉवरेन बॉण्ड जारी करना प्रतीत होता है। प्रस्तावित 10 बिलियन डॉलर का सॉवरेन निर्गमन विदेशी मुद्रा भंडार के स्टॉक का प्रबंधन करने योग्य है, जबकि वर्तमान में भारत का सॉवरेन बाह्य ऋण (सकल घरेलू उत्पाद का हिस्सा) मामूली है।

हालांकि, बाहरी उधारों में वृद्धि से अर्थव्यवस्था में जोखिम का एक अतिरिक्त तत्व जुड़ जाता है। इस तरह के कदम से मौद्रिक नीति और भी जटिल हो सकती है क्योंकि किसी भी प्रतिकूल विनिमय दर की चाल से सरकारी ऋण पर ब्याज, भुगतान का निर्माण करेगा जो पहले से ही बजटीय खर्च के एक चौथाई हिस्से पर कब्जा कर चुका है। इसलिए यह कहना जल्दबाजी होगी कि वर्तमान नीति भारत के लिए आदर्श साबित होगी या नहीं।

### भारत की विकास दर

#### आईएमएफ के अनुसार-

- हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (International Monetary Fund-IMF) ने वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक को अपडेट किया है तथा इस अपडेट में भारत की विकास दर में 0.3% अंकों की कटौती की है।
- यह घरेलू मांग के उम्मीद से कम होने को दिखाता है। भारत के विकास दर अनुमान को कम करने का प्रमुख कारण मांग की खराब स्थिति है।
- अप्रैल, 2019 में आईएमएफ ने भारत की विकास दर 7.3% रहने का अनुमान व्यक्त किया था, लेकिन अब इसने वर्ष 2019-20 में भारत की विकास दर 7% रहने का अनुमान व्यक्त किया है।
- इसके अलावा वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक (World Economic Outlook) की जुलाई में आई रिपोर्ट में वर्ष 2020-21 के लिये भी भारत के विकास दर अनुमान को पूर्व में जारी अनुमान 7.5% से घटाकर 7.2% कर दिया गया है।
- रिपोर्ट के अनुसार, भारत की अर्थव्यवस्था में 7% की दर से वृद्धि होगी, जो वर्ष 2020 में 7.2% तक पहुँच सकती है।
- दोनों वर्षों के लिये 0.3% अंकों की गिरावट अपेक्षित परिणाम से कम घरेलू मांग को दर्शाती है।
- वर्ष 2020-21 के लिये 7.2% की वृद्धि का अनुमान अक्तूबर, 2018 और जनवरी, 2019 में किये गए पूर्वानुमान की तुलना में 0.5 प्रतिशत कम है।
- इसके अलावा IMF ने विश्व के GDP विकास के अनुमान में भी 0.1% की कटौती की है। वर्ष 2019 तथा 2020 के लिये नए अनुमान क्रमशः 3.2% तथा 3.5% हैं।
- उभरते बाजारों एवं विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के विकास अनुमान में भी वर्ष 2019 के लिये 0.3 % तथा वर्ष 2020 के लिये 0.1 % की कमी की गई है। इन दोनों वर्षों के लिये संशोधित अनुमान क्रमशः 4.1% तथा 4.7% हैं।

#### क्रेडिट रेटिंग एजेंसी क्रिसिल के अनुसार-

- क्रिसिल ने चालू वित्त वर्ष में देश की आर्थिक वृद्धि दर के अपने अनुमान को 0.20 प्रतिशत से घटाकर 6.9 प्रतिशत कर दिया है।
- रेटिंग एजेंसी ने सुस्त वैश्विक वृद्धि और कमजोर मानसून जैसे जोखिमों को देखते हुए जीडीपी अनुमान घटाया है।
- भारतीय रिजर्व बैंक ने जून में 2019-20 के लिए आर्थिक वृद्धि के अनुमान को 7.2 प्रतिशत से घटाकर सात प्रतिशत कर दिया।

- घरेलू गतिविधियों में सुस्ती और वैश्विक व्यापार युद्ध को देखते हुए बैंक ने यह कदम उठाया था।
- क्रिसिल ने रिपोर्ट में कहा कि चालू वित्त वर्ष की पहली छमाही में सुस्ती रहेगी, जबकि अनुकूल मौद्रिक स्थितियाँ और खपत में वृद्धि से दूसरी छमाही को समर्थन मिलने की उम्मीद है।
- रिपोर्ट में कहा गया है कि भारतीय अर्थव्यवस्था देश-दुनिया में होने वाले घटनाक्रमों से प्रभावित होगी। ऐसे में देश की सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) वृद्धि पहले के अनुमान से 0.20 प्रतिशत घटकर 6.9 प्रतिशत रह जाने का अनुमान है।
- रिपोर्ट में गौर किया गया है कि वित्त वर्ष 2016-17 में भारतीय अर्थव्यवस्था ने 8.2 प्रतिशत की जोरदार वृद्धि हासिल की थी। इसके बाद नई नीतिगत पहलों, सुधारों को बढ़ाने और व्यापार विवाद सहित वैश्विक स्तर पर बढ़ती अनिश्चितता का असर रहा।
- पिछले साल के आखिरी में शुरू हुआ आवास, वित्त कंपनियों का संकट, आय कम रहने से घरेलू मांग में कमी के साथ साथ कमजोर धारणा और बढ़ती लागत का भी अर्थव्यवस्था पर असर पड़ा।
- इससे पहले जारी केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय (सीएसओ) के आंकड़ों के मुताबिक 2018-19 में भारत की जीडीपी वृद्धि पाँच साल के न्यूनतम स्तर तक गिर गई और जनवरी-मार्च तिमाही में यह 5.8 प्रतिशत रही।

#### विश्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार-

- सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी की वैश्विक रैंकिंग में भारतीय अर्थव्यवस्था फिसलकर सातवें नंबर पर आ गई है।
- वित्त वर्ष 2018 के लिए विश्व बैंक के आंकड़ों के मुताबिक जीडीपी के मामले में भारत सातवें नंबर पर, जबकि ब्रिटेन और फ्रांस क्रमशः पांचवें और छठे स्थान पर पहुँच गए हैं।
- साल 2017 में भारत फ्रांस को पछाड़कर आगे पहुँचा था, लेकिन इस बार फिसल गया है।
- जीडीपी के मामले में अमेरिकी अर्थव्यवस्था टॉप पर बनी हुई है। कारोबारी साल 2018 में यूएस की जीडीपी 20.5 ट्रिलियन डॉलर रही।
- अमेरिका के बाद दूसरे पायदान पर चीन है। इस दौरान चीन की जीडीपी 13.6 ट्रिलियन डॉलर रही। 5 ट्रिलियन डॉलर की जीडीपी के साथ जापान तीसरे पायदान पर है।
- ब्रिटेन और फ्रांस 2.8 ट्रिलियन डॉलर की जीडीपी के साथ इस लिस्ट में पांचवें और छठे पायदान पर हैं, जबकि भारत की जीडीपी 2.7 ट्रिलियन डॉलर दर्ज की गई।



- वित्त वर्ष 2017 में भारतीय अर्थव्यवस्था की जीडीपी 2.65 ट्रिलियन डॉलर थी, जिसने एशिया की तीसरी सबसे बड़ी उभरती इकॉनमी को विश्व की पांचवीं सबसे बड़ी इकॉनमी बना दिया था। उस दौरान यूके की जीडीपी 2.64 ट्रिलियन डॉलर और फ्रांस की 2.5 ट्रिलियन डॉलर थी।

### वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक

- यह एक सर्वेक्षण है, जिसका आयोजन तथा प्रकाशन अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा किया जाता है।
- यह भविष्य के चार वर्षों तक के अनुमानों के साथ निकट और मध्यम संदर्भ में वैश्विक अर्थव्यवस्था को प्रदर्शित करता है।
- इसके पूर्वानुमान में सकल घरेलू उत्पाद, मुद्रास्फीति, चालू खाता और दुनिया भर के 180 से अधिक देशों के वित्तीय संतुलन जैसे महत्वपूर्ण आर्थिक संकेतक शामिल हैं।

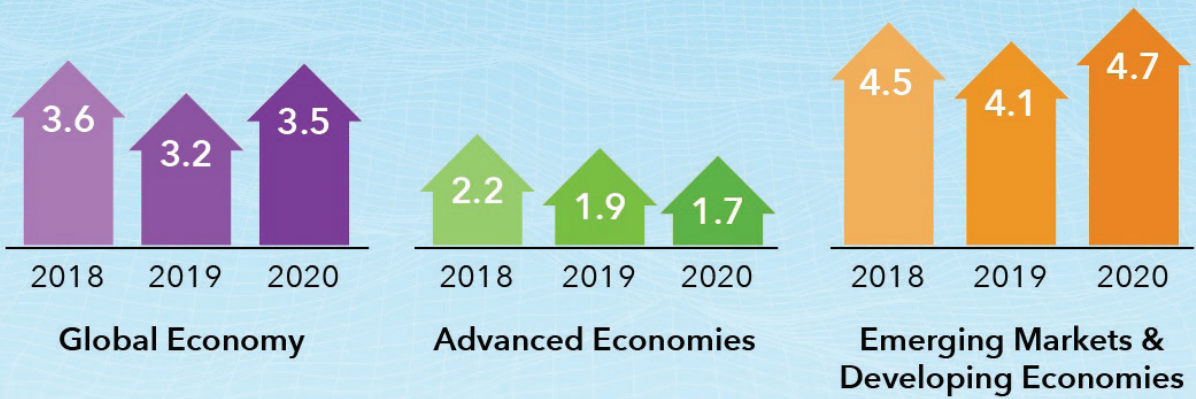
### अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष

- यह एक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्था है, जो अपने सदस्य देशों की वैश्विक आर्थिक स्थिति पर नजर रखने का कार्य करती है।
- यह अपने सदस्य देशों को आर्थिक एवं तकनीकी सहायता प्रदान करने के साथ-साथ अंतर्राष्ट्रीय विनिमय दरों को स्थिर रखने तथा आर्थिक विकास को सुगम बनाने में भी सहायता प्रदान करती है।
- इसका मुख्यालय वाशिंगटन डी.सी., संयुक्त राज्य अमेरिका में है।
- इसकी विशेष मुद्रा SDR (स्पेशल ड्राइंग राइट्स, Special Drawing Rights) कहलाती है।
- इसका उद्देश्य आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित करना, आर्थिक प्रगति को बढ़ावा देना, गरीबी को कम करना, रोजगार को नए अवसरों का सृजन करने के साथ-साथ अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को सुविधाजनक बनाना है।

WORLD ECONOMIC OUTLOOK • JULY, 2019

## GROWTH PROJECTIONS

Still Sluggish Global Growth



INTERNATIONAL MONETARY FUND • [www.IMF.org](http://www.IMF.org) • #WEO

संभावित प्रश्न ( प्रारंभिक परीक्षा )

Expected Questions (Prelims Exams)

1. हाल ही में वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जारी की गई है। इस सन्दर्भ में निम्नलिखित कथनों विचार कीजिए-

1. इस रिपोर्ट में वर्ष 2019-20 के लिए भारत की विकास दर 7 प्रतिशत रहने का अनुमान व्यक्त किया गया है।
2. 2020-21 के लिए भारत के विकास दर अनुमान को 7.5 प्रतिशत से घटाकर 7.2 प्रतिशत कर दिया गया है।
3. वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट विश्व बैंक द्वारा जारी की जाती है।

उपर्युक्त में से कौन-से कथन सत्य हैं?

- (a) 1 और 2
- (b) 2 और 3
- (c) 1 और 3
- (d) उपर्युक्त में से कोई नहीं

1. Recently the World Economic Outlook report has been released; consider the following statements-

1. In this report, India's growth rate for the year 2019-20 is estimated to be 7 percent.
2. India's growth rate for 2020-21 has been reduced from 7.5 percent to 7.2 percent.
3. World Economic Outlook Report is released by the World Bank.

Which of the above statements is/are correct?

- (a) 1 and 2
- (b) 2 and 3
- (c) 1 and 3
- (d) None of the above

संभावित प्रश्न ( मुख्य परीक्षा )

**प्रश्न:** हाल ही में जारी आई.एम.एफ. की वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट में वैश्विक विकास दर में गिरावट दर्ज की गई है और आगे भी विद्यमान रहने की भविष्यवाणी की गई है। एशिया में इसे रोकने या कम करने में प्रमुख एशियाई देशों की भूमिका का मूल्यांकन कीजिए। ( 250 शब्द )

**Q.** Recently the World Economic Outlook report of IMF was released which shows a decline in global growth rate and is predicted to continue. Evaluate the role of major Asian countries in preventing or reducing this crisis in Asia (250 Words)

**नोट :** 2 अगस्त को दिए गए प्रारंभिक परीक्षा (संभावित प्रश्न) का उत्तर 1(a) होगा।